बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 51 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 02 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

असली मुकाबला तीनों दलों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का, वर्तमान नेतृत्व क्षमता का आइना बनेंगे नतीजे

नई दिल्ली । एमसीडी के 12 वार्डों में रविवार को हुए उपचुनाव में भाजपा, आप और कांग्रेस के 36 समेत 51 उम्मीदवारों के बीच असली मुकाबला नहीं बल्कि तीनों दलों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का है। उपचुनाव परिणाम सीधे तौर पर राजधानी की तीनों प्रमुख पार्टियों के वर्तमान नेतृत्व की क्षमता, पकड़ और विश्वसनीयता का आइना बनेगा। इस कारण तीनों पार्टियों के प्रमुखों ने उपचुनाव में आम चुनाव की तरह ताकत लगाई। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने भी चुनाव में ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 11 पार्षदों के विधायक बनने और कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली की सांसद के कारण इन 12 वार्डों में उपचुनाव हुआ।

दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार से मांगा गया एक्शन प्लान

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और संबंधित अधिकारियों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अपनी कार्ययोजना पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया ताकि यह देखा जा सके कि क्या इससे कोई प्रभावी बदलाव आया है। सीजेआई कांत ने कहा कि आप अपनी कार्ययोजना पर फिर से विचार क्यों नहीं करते ताकि खुद देख सकें कि क्या आपने कोई प्रभावी बदलाव लाए हैं? और अगर लाए हैं, तो क्या वे जरूरत से कम हैं? हमें लगता है कि यह मूल्यांकन करना जरूरी है कि आपकी कोई भी कार्ययोजना प्रभावी, अप्रभावी या कम प्रभावी साबित हुई है या नहीं। इस बारे में आपकी हिचकिचाहट या आत्मविश्वास के बावजूद कि क्या आप प्रभावी बदलाव ला पाएँगे, क्या कार्ययोजना पर फिर से विचार करना सही नहीं है? अब तक आपने जो कदम उठाए हैं, उनका मूल्यांकन करें । सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि पराली जलाने के अलावा और कौन से कारक वायु प्रदूषण में वृद्धि में योगदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वर्ग (किसानों) पर दोष मढ़ना बहुत आसान है जिनका न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे पराली जलाने के अलावा अन्य कारकों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर भी विचार करने की आवश्यकता है। पराली जलाना तो आम बात थी। 4-5 साल पहले लोग नीला आसमान क्यों देख पाते थे? अब क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की हर महीने कम से कम दो बार सुनवाई करेगा। इसने स्वीकार किया कि सर्दियों के मौसम के बाद स्थिति शांत हो सकती है, लेकिन इस संबंध में, इतिहास खुद को दोहराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी। जबकि न्यायालय प्रदूषण नियंत्रण में व्यवस्थागत खामियों पर विचार-विमर्श कर रहा था, दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 299 हो गया, जो रविवार शाम 4 बजे 279 था। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दो दिनों से वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की जा रही है, जबकि रविवार को यह बहुत खराब श्रेणी में थी। शनिवार को एक्यूआई 305 से घटकर 279 हो गया था।

भाजपा अध्यक्ष की घोषणा जल्द! खरमास के बाद तेज होगी प्रक्रिया, तीन प्रमुख चेहरों पर दांव

नई दिल्ली । भाजपा में ऐसी अटकलें तेज हैं कि पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा जल्द ही हो सकती है। बिहार में एनडीए की जदीत के बाद अटकलें तेज हैं कि राज्य में अहम भूमिका निभाने वाले एक कैबिनेट मंत्री, मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की जगह ले सकते हैं। हालाँकि, इस पद के लिए कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी चर्चा में हैं। सूत्रों ने खुलासा किया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में संपन्न तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में आरएसएस के शीर्ष नेताओं के बीच इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ। सूत्रों के अनुसार, पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय पाने वाले एक वरिष्ठ आरएसएस नेता को भी पार्टी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। नड्डा को 2019 में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनावों तक बढ़ा दिया गया था। 29 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं और केवल उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में ही चुनाव अभी जारी हैं, ऐसे में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुँच गई है। जनवरी 2026 तक नए पार्टी अध्यक्ष का चयन होने की उम्मीद है। पार्टी के एक वरिष्ठ सूत्र ने संकेत दिया कि 14 जनवरी के बाद, जब हिंदू पंचांग में अशुभ माने जाने वाले खरमास का समापन होगा और शुभ चरण शुरू होगा, प्रक्रिया में तेजी आएगी। भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने कहा, सभी तैयारियाँ और प्रक्रियाएँ राज्यों में संगठनात्मक चुनावों के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रही हैं, और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी 2026 तक होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि चुनावों के लिए निर्वाचक मंडलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 29 राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में औपचारिकताएँ अभी भी जारी हैं। इस बीच, भगवा हलकों में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, जो वर्तमान में सेवा विस्तार पर हैं, के उत्तराधिकारी के रूप में तीन नाम चर्चा में हैं। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शुक्रवार को बताया, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान उन प्रमुख नामों में शामिल हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इनमें से, आरएसएस और अमित शाह, दोनों के करीबी माने जाने वाले मौर्य और बिहार चुनाव अभियान के दौरान चुनाव प्रभारी रहे प्रधान, सबसे प्रमुख दावेदारों में उभरे हैं।

सरकार ने संसद में स्वीकारा: विमानों के सिग्नल से छेड़छाड़, दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर जीपीएस स्पूफिंग की कोशिश

नई दिल्ली।

नवंबर महीने की शुरुआत में देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर हवाई सेवाओं के संचालन में भारी परेशानी देखने को मिली थी। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर करीब 800 उड़ानें प्रभावित हुईं। इस दौरान एटीसी की तरफ से ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी बताया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने संसद में एक लिखित बयान में स्वीकार किया है कि दिल्ली समेत देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर जीपीएस स्पूफिंग की समस्या हुई थी, यानी इन सभी हवाई अड्डों पर आने और यहां से उड़ान भरने वाले विमान जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हुए हैं।

दिल्ली में क्या हुआ?

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किनजारापु ने बताया कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआई) के पास उड़ने वाले कुछ विमानों ने जीपीएस स्पूफिंग की सूचना दी। यह समस्या रनवे 10 पर जीपीएस आधारित लैंडिंग के दौरान दर्ज की गई।

स्पूफिंग का पता लगते ही तुरंत वैकल्पिक प्रक्रियाएं अपनाई गईं, जिससे विमान सुरक्षित रूप से उतरे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि दूसरे रनवे पूरी तरह सुरक्षित रहे क्योंकि वहां पारंपरिक नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध थे। उड़ान संचालनों पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा।

समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं

सरकार के अनुसार, जीपीएस जामिंग/स्पूफिंग की रिपोर्ट नवंबर 2023 से अनिवार्य की गई है। इसके बाद देश के कई बड़े हवाईअड्डों से यह समस्या लगातार सामने आ रही है। इसमें कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बंगलूरू और चेन्नई एयरपोर्ट शामिल हैं। इन सभी जगहों पर जीएनएसएस इंटरफेरेंस की शिकायतें मिल रही हैं।

क्या है जीपीएस स्पूफिंग?

जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर हमला है, जिसमें नकली सिग्नल भेजकर किसी भी डिवाइस को गलत लोकेशन दिखाई जाती है। जैसे आपके फोन की लोकेशन अचानक चार किमी दूर दिखने लगे, वैसा ही विमानों के साथ होता है। जब यह विमान के साथ होता है, तो उसका नेविगेशन सिस्टम गलत दिशा में जा सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है।

जांच और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

सरकार की ओर से इस समस्या की पहचान के बाद कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें डीजीसीए ने जीएनएसएस इंटरफेरेंस से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की। वहीं जीपीएस स्पूफिंग की रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए नई एसओपी लागू की गई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने डब्ल्यूएमओ को इंटरफेरेंस के स्रोत का पता लगाने को कहा और डब्ल्यूएमओ से संसाधन बढ़ाने और संदिग्ध स्थानों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए।

साइबर सुरक्षा भी हुई मजबूत

एविएशन सेक्टर पर बढ़ते रैनसमवेयर और मैलवेयर जैसे साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए- एएआई ने आईटी नेटवर्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर में उन्नत साइबर सिक्योरिटी लागू की है। सभी उपाय एनसीआईआईपीसी और सीईआरटी-आईएन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। वहीं खतरे के प्रकार में बदलाव के साथ सुरक्षा सिस्टम लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं।

पहले सरकार ने क्या दिया था आंकड़ा

वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद में एक आंकड़ा पेश किया था। सरकार ने लोकसभा में बताया था कि नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच 465 जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र (अमृतसर और जम्मू) में दर्ज की गईं।

वहीं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में 4.3 लाख जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2023 की तुलना में 62फीसदी अधिक हैं।

कुत्ते को संसद ले आईं रेणुका चौधरी, सत्तापक्ष पर साधा निशाना- असली काटने वाले तो यहां बैठे हैं

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी सोमवार को एक कुत्ते को संसद परिसर में ले आईं, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह आवारा है। उन्होंने अन्य सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए दावा किया कि असली कुत्ते संसद में बैठे हैं और रोज़ लोगों को काट रहे हैं। चौधरी ने बताया कि उन्होंने सुबह संसद जाते समय इस पिल्ले को बचाया था। उन्होंने एक स्कूटर-कार की टक्कर देखी और देखा कि पिल्ला सड़क के पास घूम रहा था। कुत्ते को चोट न लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए वह उसे अपनी कार में साथ ले आईं। कुत्ता गाड़ी के अंदर ही रहा और कांग्रेस सांसद को कार से उतारने के कुछ देर बाद ही चला गया। चौधरी ने एएनआई को बताया क्या कोई कानून है? मैं जा रही थी। एक स्कूटर और कार की टक्कर हो गई। यह छोटा पिल्ला सड़क पर घूम रहा था। मुझे लगा कि यह पहिए से टकरा जाएगा। इसलिए मैंने उसे उठाया, कार में रखा, संसद आई और वापस भेज दिया। कार चली गई, और कुत्ता भी। तो इस चर्चा का क्या मतलब है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के किसी भी सांसद का नाम लिए बिना, चौधरी ने सत्तारूढ़ दल पर तंज कसते हुए कहा कि असली कुत्ते संसद में बैठे हैं, और वैसे भी इस पर कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि असली काटने वाले संसद में बैठे हैं। वे सरकार चलाते हैं। हम एक मूक जानवर की देखभाल करते हैं, और यह एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया है। क्या सरकार के पास और कोई काम नहीं है? मैंने कुत्ते को घर भेज दिया और कहा कि इसे घर पर ही रखें... हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो संसद में बैठकर हमें रोज़ काटते हैं। इस बीच, संसद के शीतकालीन सत्र में, खासकर लोकसभा में, विपक्षी सांसदों ने देश भर में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर बार-बार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सदन में वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए, वहीं अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी सांसद संध्या राय ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच, सितंबर में कार्यभार संभालने वाले नए राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के अभिनंदन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस चर्चा में कई राज्यसभा सांसदों ने, पार्टी लाइन से हटकर, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का सदन में स्वागत किया।

न्यूट्रल रेगुलेटर और डिजिटल लोकतंत्र की चुनौती

वैश्विक स्तरपर सोशल मीडिया आज दुनियाँ के लोकतंत्र की सबसे प्रभावशाली, और कई बार सबसे खतरनाक, ताकत के रूप में उभरा हैसूचना के त्वरित प्रसार ने जहां संवाद को नई ऊर्जा दी है, वहीं गलत सूचना, घृणास्पद भाषण, मानहानि सामग्री,वैचारिक उन्माद और संस्थानों के प्रति अविश्वास जैसी समस्याएँ भी अत्यंत तीव्रता से बढ़ी है। भारत जैसे व्यापक जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश में यह चुनौती और अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि विविधता, राजनीतिक सक्रियता और इंटरनेट की तीव्र पहुंच मिलकर सूचना के प्रसार को बेकाबू बना देते हैं।ऐसे समय में एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि ऐसे समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार को दिए गए नए दिशा- निर्देश न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर निरंतर बढ़ रहे हानिकारक कंटेंट को केवल पोस्ट-फैक्टो यानी घटना होने के बाद हटाने की प्रक्रिया से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।यह एक ऐतिहासिक टिप्पणी है, क्योंकि अब तक दुनिया के अधिकांश देशों ने सोशल मीडिया को मुख्य रूप से इसी पोस्ट- रेगुलेशन मॉडल पर चलाया है, जबकि भारत पहली बार प्रि-स्क्रीनिंग मॉडल पर विचार कर रहा हैकेंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे अश्लील और हानिकारक कंटेंट को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक नया नियामक ढांचा तैयार कर रहा है। सरकार ने कोर्ट से चार सप्ताह का और समय मांगा है ताकि इन नए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर लोगों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए जा सकें। साथियों बात अगर हम इस केस को समझने की करें तो, मीडिया में जानकारी आई कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट के अनुसारसोशल मीडिया पर वायरल होने वाला कंटेंट आधुनिक समय का सबसे कठिन सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा संकट है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। यह गति कई बार इतने बड़े स्तर पर हानि पहुँचाती है कि सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं बचता। अदालत ने कहा कि अगर किसी कंटेंट को हटाने से पहले ही वह समाज में तनाव, नफरत या हिंसा का कारण बन जाए,तो ऐसीस्थिति में पोस्ट-फैक्टो कार्रवाई का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं रह जाता। ऐसे में केवल सुधारात्मक उपाय नहीं, बल्कि सुरक्षा-आधारित निवारक उपाय की आवश्यकता होती हैइसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सोशल मीडिया कंटेंट के अपलोड होने से पहले प्रि-स्क्रीनिंग मैकेनिज्म का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया। यह निर्देश केवल प्रशासनिक नहीं,बल्कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तकनीकी नैतिकता के बीच एक नए संतुलन की खोज का संकेत भी है। साथियों बात अगर हम अदालत का यह दृष्टिकोण विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है इसको समझने की करें तो यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक समाचार एजेंसी,प्रसारण संस्थान और जनसंचार माध्यम केंद्रित स्वरूप के रूप में देखता है।

पारंपरिक मीडिया पर प्रि- सेंसरशिप या प्रि-अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह लागू नहीं रही,क्योंकि इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मंच माना जाता रहा है। किंतु वर्तमान समय में व्यक्तिगत अभिव्यक्तियाँ गण-शांति का रूप ले चुकी हैं और उनका प्रभाव कई देशों में चुनाव परिणामों,जनदंगों, दंगों, बैंकिंग संकटों,स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और आतंकवादी गतिविधियों तक में देखा गया हैसुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब सोशल मीडिया कंटेंट समाज की संवेदनशीलता, सुरक्षा और व्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रहा है, तब उसके लिए नए प्रकार की नियामक संरचना आवश्यक है। यही कारण है कि कोर्ट ने सरकार को हथियार थमाते हुए,जैसा कि मीडिया ने इसे वर्णित किया,एक कठोर लेकिन जरूरी ढांचे की कल्पना करने को कहाइसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए कोई सेल्फ- स्टाइल्ड या स्वयंभू संस्था पर्याप्त नहीं है। अभी तक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने स्वयं के कम्युनिटी गाइडलाइंस और फैक्ट-चेकिंग मैकेनिज्म के आधार पर कंटेंट मॉडरेशन करते रहे है। परंतु अदालत के अनुसार ये संस्थाएँ न तो पारदर्शी है, न निष्पक्ष, और न ही बाहरी प्रभावों से मुक्त। इनका संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनके अपने हित, बाजार रणनीतियाँ और राजनीतिक दबाव हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत को एक ऐसी न्यूट्रल,स्वतंत्र,और संविधान -आधारित रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता है, जो न उद्योग के हितों के प्रति झुकी हो और न किसी राजनीतिक प्रभाव के तहत काम करेयह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है, क्योंकि दुनिया में अभी तक केवल कुछ ही देशों ने सोशल मीडिया के लिए स्वतंत्र रेगुलेटर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बेंच, की टिप्पणियों को समझने की करें तो, भारत को सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हों। इस चर्चा के दौरान सीजेआई ने एससी/एसटी एक्ट का उदाहरण दिया। यह एक कठोर कानून है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के प्रति जाति-आधारित अपमान या हिंसा के मामले में स्पष्ट और सख्त दंड तय है। इसी मॉडल को डिजिटल स्पेस में लागू करने का संकेत अदालत ने देते हुए कहा कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति या अन्य संवेदनशील समुदायों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर अपलोड होती है, तो उस पर केवल रिपोर्ट और डिलीट करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह टिप्पणी पहली बार डिजिटल अपराधों को पारंपरिक संवेदनशीलता -आधारित अपराधों की श्रेणी में रखने का संकेत देती है, जो भारत के सामाजिक ढांचे के संदर्भ में अत्यंत क्रांतिकारी विचार हैसुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस संदर्भ में की जब कई इन यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में कथित रूप से दिव्यांग व्यक्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जिनके विरुद्ध कई राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

यूट्यूबर्स ने इन एफआईआर को चुनौती देते हुए कहा कि कंटेंट हल्के हास्य के रूप में था और मामला विवादास्पद नहीं होना चाहिए। लेकिन अदालत का दृष्टिकोण इस पर स्पष्ट था कि डिजिटल माध्यम पर अपलोड की गई कोई भी टिप्पणी केवल मनोरंजन या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के दायरे में सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उसका समाज सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यापक होता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब महज मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि जनमत निर्माण के सबसे शक्तिशाली स्रोत बन चुके हैं। इसलिए इन पर मौजूद कंटेंट के लिए जिम्मेदारी भी समान रूप से बढ़ती है। साथियों बात अगर हम इस मामले को अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में देखे तो सोशल मीडिया रेगुलेशन की यह बहस पूरी दुनियाँ में चल रही हैयूरोप में डिजिटल सर्विसेज एक्ट, अमेरिका में सेक्शन 230 पर चल रही बहस, ऑस्ट्रेलिया में न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड और कनाडा में ऑनलाइन हार्म्स एक्ट ये सभी इस बात का संकेत है कि सोशल मीडिया अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा सुरक्षा, गोपनीयता, गलत सूचना और लोकतांत्रिक स्थिरता का प्रश्न बन चुका है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच नए संतुलन का निर्माण करना चाहती है। कोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया की स्वतंत्रता तभी तक स्वीकार्य है जब तक वह किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या राष्ट्र की गरिमा और सुरक्षा को आघात न पहुंचाए। यदि कोई कंटेंट इस सीमा का अतिक्रमण करता है, तो उसे प्रि-स्क्रीनिंग के माध्यम से रोका जाना चाहिए।प्रि-स्क्रीनिंग मैकेनिज्म का प्रस्ताव भी काम कर सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वचालित फिल्टरिंग, ह्यूमन मॉडरेशन, स्वतंत्र सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसी की स्क्रीनिंग,और प्लेटफॉर्म-आधारित कंप्लायंस मॉडल इन सभी की भूमिका हो सकती है। हालांकि इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव, यह कौन तय करेगा कि क्या आपत्तिजनक है, क्या यह सेंसरशिप की ओर नहीं बढ़ जाएगा, क्या यह तकनीकी रूप से संभव है कि भारत में रोजाना अपलोड होने वाले करोड़ों पोस्टों को पहले से स्क्रीनिंग की जाए ये प्रश्न स्वाभाविक है।

सम्पादकीय...

झंडारोहण ईवेंट

अब तो मान लो कि राम राज्य आ चुका है। अब तो अयोध्या में झंडारोहण का ईवेंट भी हो गया। यानी राम मंदिर फाइनली पूरा भी हो गया। अब इसमें बाल की खाल मत निकालने लग जाना कि मंदिर अगर 2025 के 25 नवंबर को फाइनली अब पूरा हुआ है, तो क्या मंदिर तब अधूरा था, जब 2024 के आम चुनाव का प्रचार अभियान बाकायदा शुरू करने से पहले, मोदी जी ने भागवत के साथ जुगल जोड़ी में, इससे भी ज्यादा गा-बजा कर और सरकारी दफ्तरों तक में छुट्टी करवा कर, उसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ईवेंट किया था तो क्या शंकराचार्यों की आपत्ति सही थी कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ईवेंट कराया जा रहा था, जो शास्त्र विरुद्ध था क्या विरोधियों की आलोचना सही थी कि आम चुनाव में फायदा उठाने के लिए, जबर्दस्ती अधूरे मंदिर का उद्घाटन कराया जा रहा था नहीं, हर्गिज नहीं! मोदी जी का किया उद्घाटन असमय कैसे हो सकता है मोदी जी के किसी काम का टैम गलत नहीं हो सकता है। मोदी जी को जब जो करना होता है, वही उसे करने के लिए सही समय होता है। मोदी जी ने जब पौने दो साल पहले उद्घाटन किया था, मंदिर तब भी पूरा ही था। बस इतनी बात है कि अब झंडा लगने के साथ, मंदिर फाइनली पूरा हो गया है। वैसे हम तो कहते हैं कि भक्तों को इसे भी फाइनली फाइनल मानने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कल को मोदी जी मंदिर में कुछ और जोड़ने का ईवेंट करना चाहेंगे तो क्या कोई उन्हें रोक लेगा और कुछ नहीं तो रंगाई-पुताई से लेकर मरम्मत तक के ईवेंट तो कभी भी कराए ही जा सकते हैं! देखा ना, बाल की खाल निकालने वालों का जिक्र भर आने से हम भटक कर कहां से कहां पहुंच गए। इतनी मुश्किल से फाइनली मंदिर पूरा हुआ है, और मुओं ने अभी से रंगाई-पुताई और मरम्मत की चर्चा निकलवा दी। नेगेटिविटी को मोदी जी, भागवत जी वगैरह इसीलिए तो इतना बुरा कहते हैं। वर्ना सकारात्मकता होती तो उद्घाटन के टैम पर मंदिर के अधूरेपन को देखने के बजाए, क्या यही नहीं देखा जाता कि मोदी जी ने भक्तों के इंतजार के पूरे पौने दो साल कम करा दिए जो मंदिर 2025 के आखिर में कहीं जाकर चालू होना था, उसे 2024 के शुरू में ही चालू करा दिया। पर नकारात्मकता के चक्कर में विरोधियों तो विरोधियों, परंपरावादियों तक ने आम चुनाव की टाइमिंग तो देखी, पर भक्तों के इंतजार में पौने दो साल की कमी की टाइमिंग नहीं की। वर्ना मोदी जी का क्या था, उद्घाटन के ईवेंट के लिए मंदिर के झंडे वगैरह के साथ, फाइनली पूरा होने तक तो इंतजार कर ही सकते थे उद्घाटन के इवेंटों की कमी थी क्या पर यह मोदी का भारत है। मोदी के भारत के भक्त अधीर और सबसे बढ़कर राम काज करने के लिए अधीर हैं। पौने दो साल छोड़ो, मोदी के भारत के भक्त तो पौने दो पल का भी इंतजार करना पसंद नहीं करते। पहले वालों के जमाने के भक्त थोड़े ही हैं जो साढ़े चार सौ साल से ज्यादा से बस इंतजार ही तो कर रहे थे कि इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में कोई मोदी आएगा, जो अपने राज के ग्यारहवें वर्ष में रामलला को उंगली पकड़ाकर, उनकी घर वापसी कराएगा! पहले वाले भक्तों ने अब वालों जैसी अधीरता दिखायी होती, तो क्या अंगरेजों ने ही रामलला की घर वापसी नहीं करा दी होती अंगरेज अगर अयोध्या में मस्जिद-मंदिर का झगड़ा खड़ा कर सकते थे, तो क्या रामलला की वापसी भी नहीं करा सकते थे काश रामलला की आजादी के लिए तभी हिंदुओं को ढंग से जगाया गया होता। काश, ए ओ ह्यूम ने तब कांग्रेस की जगह आरएसएस की स्थापना होती! खैर, मुद्दे की बात यह है कि फाइनली पूरा होने समेत, राम मंदिर के उद्घाटन के तीन-तीन ईवेंट तो मोदी जी-भागवत जी की जुगल जोड़ी के ही कर कमलों से हो चुके हैं। सबसे पहले, मंदिर बनवाने के सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद, शिला पूजन का ईवेंट। उसके चार साल बाद, प्राण प्रतिष्ठा का ईवेंट। और अब, झंडारोहण का ईवेंट। और यह तो तब है जबकि राम मंदिर का शिलान्यास तो विवादित क्षेत्र के एक हिस्से में, अस्सी के दशक के आखिर में ही हो चुका था यानी मोदी जी को सारथी बनाकर निकली आडवाणी जी की रथ यात्रा से भी पहले। पर वो सब मोदी-पूर्व भारत की बातें हैं, जब भारत सांस्कृतिक प्रसुप्तावस्था में था। ऐसे तो मंदिर भी कहीं गया नहीं था, वह तो हमेशा से वहीं मौजूद था; तब भी जब मस्जिद को हटाने के जोश में कार सेवकों ने मस्जिद में एकाएक प्रकट हुए मंदिर को भी हटा दिया था। टेंपरेरी वाले मंदिर का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक, सब एक साथ तब भी हुआ ही होगा। मगर हड़बड़ी में, बिना किसी ईवेंट के। मोदी पूर्व-युग का उद्घाटन भी कोई उद्घाटन है, लल्लू! वैसे भी मंदिर भले ही हमेशा रहा हो, रामलला जरूर भूल-भटककर या रूठकर कहीं और चले गए थे। तभी तो मोदी जी पौने दो साल पहले उन्हें उंगली पकड़कर वापस लाए थे। मोदी जी की तस्वीर वाले पोस्टर झूठ थोड़े ही बोलते हैं। और बात सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर के फाइनली उद्घाटन की ही थोड़े ही है। और बात सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर के फिर-फिर उद्घाटन भर की भी नहीं है। अगले दिन, कर्नाटक में उडुपी में राजा बाबू ने श्रीकृष्ण का मोर मुकुट धारण कर, सामूहिक गीता पाठ भी किया और गीता का उपदेश भी दिया। और हां! उडुपी में कृष्ण वेश धारण करने से पहले राजा बाबू को तीन किलोमीटर का रोड शो करना नहीं भूला, जबकि कर्नाटक में अभी चुनाव दूर है। और बाद में उसी शाम गोवा में पुर्तगाली मठ में 77 फीट ऊंची राम की प्रतिमा का उद्घाटन भी कर दिया जो दुनिया की राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बतायी जाती है, जो कांसे की बनी है। और इतना सब सिर्फ दो दिन में। यानी ब्राह्मणवादी धार्मिकता की बाढ़ के बीच-बीच में राजनीतिक प्रचार के टापू, जिन पर प्रधानमंत्री फुल टाइम पुजारी की मुद्रा में नाचते और कथावाचक की बोली में उपदेश में देते हुए। भारत वालो अब तो मोदी जी का कहा सच मान लोह्न चाहे अच्छे दिन कभी न आएं, चाहे अमृतकाल कोरा जुमला रह जाए। और विकसित भारत झांसा, पर मोदी जी राम राज्य ले आए हैं। और कितनी धर्मबाजी चाहिए, राम राज्य के लिए! अब इस सब में टाटा, रिलायंस, अडानी वगैरह की सेवा की किटकिट मत घसीट लाना। और कभी नोटबंदी, तो कभी लॉकडाउन और अब एसआईआर के जरिए पब्लिक को जान हलकान किए जाने को भी नहीं। वोट चोरी वगैरह से लेकर ऊंची रंगदारी वसूली तक, हद दर्जे की बेशर्मी को तो हर्गिज-हर्गिज नहीं। माना कि उस वाले राम राज्य में यह सब नहीं था, पर किसने कहा कि यह उस वाले राम राज्य की नकल भर है। बेशक, राम राज्य है, पर इसमें मोदी तत्व का भी समावेश है, अपनी ओरिजिनालिटी भी तो है। सिंपल राम राज्य नहीं, यह उससे आगे की चीज है—यह राम राज्य 2.0 है प्यारे!

भारत को मिले नए बाजार

अमेरिका द्वारा भारी-भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद विशेषज्ञों ने बहुत सी चिंताएं जताई थीं। तब से ही भारत ने नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी थी। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय वस्तुओं का निर्यात दबाव में है लेकिन भारत ने आपदा में भी अवसर तलाश लिया है।

एक अच्छी खबर यह है कि भले ही अमेरिका को निर्यात में गिरावट आई है, वहीं एशियाई, पश्चिम एशियाई, जर्मनी और कुछ यूरोपीय संघ के देशों ने भारत के लिए सम्भावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल सितम्बर में अमेरिका को रत्न एवं आभूषण निर्यात में 76 प्रतिशत तक की गिरावट आई जबकि कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात में केवल 1.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात में 79 प्रतिशत, हांगकांग को 11 प्रतिशत और बैल्जियम को 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह भारत ने रत्न एवं आभूषण, झींगा, ऑटो कम्पोनेंट और इलेक्ट्रिक मशीनरी जैसे कई उत्पाद एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भेजने में सफलता हासिल की। ऑटो कंपोनेंट्स में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला, जिनका अमेरिका को निर्यात सितंबर में 12 प्रतिशत गिरा, लेकिन जर्मनी, यूएई और थाईलैंड को निर्यात से कुल ऑटो कंपोनेंट निर्यात में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समुद्री उत्पादों में सितंबर में 25 प्रतिशत और अक्टूबर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण चीन (लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि), जापान (37 प्रतिशत), थाईलैंड (लगभग 70 प्रतिशत) और यूरोपीय संघ को निर्यात में वृद्धि थी। इससे यह धारणा पुष्ट होती है कि एशियाई क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों सहित दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का लाभ उठाकर, वाशिंगटन डीसी के साथ व्यापार समझौता जल्द ही फलदायी न होने पर इस झटके को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कम-मार्जिन वाले, श्रम-प्रधान उत्पाद खंड जैसे सूती वस्त्र, खेल के सामान, कालीन और चमड़े के जूते, जिन्हें चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, अपने शिपमेंट में विविधता लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि अमेरिकी टैरिफ का दीर्घकालिक प्रभाव असमान हो सकता है, जिससे देश भर में संचालित छोटी इकाइयों पर अधिक असर पड़ सकता है। कम मार्जिन वाले उत्पाद आमतौर पर कार्यशील पूंजी के तनाव और विदेशों में इकाइयां स्थापित करने में असमर्थता के कारण व्यापार-संबंधी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हालांकि खेलों के सामान, सूती वस्त्र, चमड़े के जूतों के निर्यात में भारत को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिका द्वारा टैरिफ वार शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू किए। जिससे अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि एक साल पहले यह 5.6 प्रतिशत थी, जो आरबीआई और आम अनुमानों से कहीं अधिक है। बढ़ती निजी खपत, निवेश और अमेरिकी टैरिफ के आगे उत्पादन और निर्यात में तेजी के कारण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। ग्रामीण मांग में वृद्धि हुई। उच्च कृषि उत्पादन, स्थिर कृषि आय और ग्रामीण जिलों में श्रम बाजार की स्थिति में सुधार ने निजी उपभोग को मजबूत किया। आंकड़ों से यह स्वीकार किया जा सकता है कि भारत की विकास यात्रा वापिस पटरी पर आ गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, दिलचस्प बात यह है कि इस अवधि के दौरान अन्य देशों को भारत के व्यापारिक निर्यात का हिस्सा काफी बढ़ गया है, जो हमारे निर्यात बास्केट के विविधीकरण को दर्शाता है, जिसमें यूएई, चीन, वियतनाम, जापान और हांगकांग के साथ-साथ बंगलादेश, श्रीलंका और नाइजीरिया भी विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में शीर्ष गंतव्यों में शामिल हैं। तो, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गंतव्य अब भारत से खरीद करने के बाद अमेरिका को अधिक निर्यात कर रहे हैं'' मोती और कीमती तथा अर्धकीमती पत्थरों के अमेरिकी आयात में आस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी-अगस्त 2025 में 9 प्रतिशत हो गई है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। उम्मीद तो इस बात की है कि आने वाले दिनों में कोई सम्मानजनक सहमति बन जाएगी। चुनौतियों के बावजूद भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने का टैग बरकरार रखा है। फिलहाल आंकड़े सुकून देने वाले हैं कि उपभोग, निवेश और विनिर्माण में पुनरुद्धार के साथ भारत के विकास इंजन अब अधिक व्यापक आधारित हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां विकास की उम्मीदें धुंधली कर सकती हैं। अभी हमें बहुत लम्बा रास्ता तय करना है। दुनिया में भूराजनीतिक संघर्ष और वित्तीय बाजार में अस्थिरता पूंजी प्रवाह और निवेश की गति को धीमा कर सकती है लेकिन भारत को मिल रहे नए बाजार उम्मीदों की उड़ान पंख दे रहे हैं।

सिकुड़ते गांव-फैलते शहर

अक्सर यह बात कही और सुनी जाती है कि दुनिया के हर छोटे और बड़े शहर में आबादी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कुछ खास शहरों की आबादी ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। इस मामले को लेकर यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो दुनिया की आबादी पर आधारित है ने चौंकाने वाले आंकड़े सबके सामने रखे हैं। यूएन वर्ल्ड अरबनाइजेशन प्रोसपेक्टस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में अगस्त तक पूरी दुनिया की शहरी आबादी 81 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और गांव की आबादी 19 प्रतिशत रह गयी है। कभी 2018 में दुनिया के शहरों में आबादी का प्रतिशत 55 था जो आज की तारीख में 81 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि शहरी इलाके भारी भीड़ की परिभाषा बन रहे हैं और सभी गांव का दुनिया में स्वरूप सिमट रहा है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो स्थिति यहां भी चौंकाने वाली है क्योंकि यहां भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान के गांव से लोग अब शहरों की तरफ भाग रहे हैं। लिहाजा वहां आबादी बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि गांव में आज की तारीख में सुविधाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं तो उनका शहरीकरण हो रहा है। यानी कि हमारे गांव का जो परम्परागत स्वरूप हुआ करता था वह तेजी से सिमट रहा है सचमुच यह चौंकाने वाली बात है। हालांकि यूएन की रिपोर्ट में शहरीकरण की लहर के तेजी से बढ़ने में लोगों के ज्यादा पैमाने पर शिक्षित होने, बेहतर रोजगार होने की बात कही गयी है। शहर के प्रति एक क्रेज लोगों को गांव से पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। शहरी विकास अच्छी बात है लेकिन ग्रामीण विकास के साथ-साथ संतुलन बना रहना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत जैसे देशों में शिक्षा और रोजगार के ज्यादा अवसर शहरों से ही जुड़े हैं। इस कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में पलायन तेजी से हुआ है। जबकि गांव में विकास उन्हें शहरीकरण के रूप में स्थापित कर रहा है। हमारा यह मानना है कि संतुलन हर सूरत में बना रहना चाहिए। यह सच है कि उत्तर भारत में लोगों का भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली के प्रति क्रेज बढ़ा है क्योंकि दिल्ली में यहां सुविधाएं है लेकिन यह भी सच है कि इसी पंजाब और हरियाणा के अनेक गांव अब शहरीकृत स्वरूप ले चुके हैं और आधुनिकता के लिबास में नजर आते है। कभी दिल्ली से सटे सोनीपत, राई, गुरुग्राम से अनेक गांव राजधानी से सटे हुए थे उधर यूपी में शामली, गाजियाबाद, हापुड़, मोदी नगर से सटे हुए थे लेकिन अब उनका शहरीकृत स्वरूप चौंकाने वाला है। दिल्ली में नजफगढ़, नरेला, अलीपुर के अनेक गांव अपनी ग्रामीण पहचान रखते थे। लेकिन अब सब के सब दिल्ली का एक भीड़भाड़ वाला नजारा पेश करते है। पुराने गांव के छोटे शहर और पृष्ठभूमि जो अपनी परंपरागत पहचान रखती थी वह अब शहरीकृत सुविधाओं में बदल चुकी है। गांव में शिक्षा और व्यापार के नाम पर वह सुविधाएं नहीं थी जो शहरों में आधुनिक पब्लिक स्कूलों, कालेजों और बड़े-बड़े मॉल्स के रूप में दिखाईदेती है। कितने ही नेशनल हाईवेज पर अब आसमान छूती इमारतें दिखाई देती है जिन्हें बड़े-बड़े मॉल का नाम दिया गया है। कई किलोमीटर तक फैले हुए हरियाली जमीन का नजारा पेश करते खेत खलिहान अब पत्थरों की इमारतों में बदलते नजर आ रहे है। सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए।

भारत का आर्थिक विकास- सहकारिता से समृद्धि की ओर

प्रह्लाद सबनानी।

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन करते हुए, ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिक आपस में भाई-चारे के साथ मिलजुलकर रहते आए हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो सहकार की भावना हम भारतीयों के डीएनए में है। इसी विषय के दृष्टिगत एक बार पुनः आज भारत के प्रत्येक गांव को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने की लिए समस्त गांवों को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सहकार से समृद्धि का नारा भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिया गया है। भारत में आज सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि भारत में सहकारी समितियां, स्व-सहायता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, न्याय एवं एकजुटता जैसे भारतीय मूल्यों के आधार पर कार्य करतीं हुई दिखाई देती हैं। साथ ही, जिन 7 सिद्धांतों के आधार पर इन समितियों के कार्य करने की अपेक्षा रहती है, उससे इन समितियों के सफल होने की सम्भावना बढ़ जाती है। यह 7 सिद्धांत हैं - खुली और स्वैच्छिक सदस्यता; लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों की भागीदारी; सदस्यों की आर्थिक भागीदारी; स्वायत्तता और स्वतंत्रता; शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना कोआपरेटिव के बीच सहयोग; समुदाय के प्रति सरोकार। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्ण मिलजुल कर समान स्तर पर आपसी आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते है जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। समृद्धि केवल धन-संपत्ति से कहीं अधिक है; यह तब होती है जब सभी लोगों को फलने-फूलने का अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समृद्धि एक समावेशी समाज पर आधारित होती है, जिसमें एक मजबूत सामाजिक अनुबंध होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करता है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाना और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसा संगठन है जो सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 से हुई है एवं तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है। कुछ अत्यधिक सफल रही है, जैसे अमूल डेयरी, परंतु इस प्रकार की सफलता की कहानियां बहुत कम ही रही हैं। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से सफल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। बल्कि, भारत में सहकारिता आंदोलन में कई प्रकार की कमियां ही दिखाई दी है। देश की अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डालर के आकार का बनाना है तो देश में सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की जा रही है। भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो ध्यान में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए है। उक्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत है और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे है जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती है। तीसरी वे है जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में महिला सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं इनकी संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई है, इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यतः देश में समुद्र के आसपास के इलाकों में स्थापित की गई है। देश में बुनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई है, इनकी संख्या भी लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। संचालन और कार्यों की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः छह प्रकार की सहकारी समितियां होती है। इनमें उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पादक सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, कृषक सहकारी समितियां, ऋण सहकारी समितियां और सहकारी आवास समितियां शामिल हैं। उक्त वर्णित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उक्त समस्त आंकड़े वर्ष 2021-22 तक के हैं। 29 जून, 2022 को भारत सरकार द्वारा 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिति लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई है, जिसे आज भी सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में सामान्यतः निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं।

सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जैसे, सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे है एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय समय पर उजागर होती रही हैं। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूंजी बाजार से पूंजी जुटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक चूंकि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था एवं केंद्र सरकार द्वारा अब किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने में कसावट आएगी एवं इन संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बन जाएगा जिसके चलते इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में भी निश्चित ही सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। अब हमें दूध के पावडर के आयात की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु दूध के उत्पादन के मामले में भारत के कुछ भाग हीं, जैसे पश्चिमी भाग, सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के उत्तरी भाग, मध्य भाग, उत्तर-पूर्व भाग में दुग्ध उत्पादन का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है। जबकि ग्रामीण इलाकों में तो बहुत बड़ी जनसंख्या को डेयरी उद्योग से ही सबसे अधिक आय हो रही है। अतः देश के सभी भागों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। केवल दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं होगा। डेयरी उद्योग को अब पेशेवर बनाने का समय आ गया है। गाय एवं भैंस को चिकित्सा सुविधाएं एवं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, आदि समस्याओं का हल भी खोजा जाना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय को दुगना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करनी होगी। इससे खाद्य सामग्री की बर्बादी को भी बचाया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत फल एवं सब्जियों का उत्पादन उचित रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन किया जाना भी अब समय की मांग बन गया है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मकानों के अभाव में बहुत बड़ी जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। अतः इन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा मकानों को बनाने के काम को गति दी जा सकती है। देश में आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंज्यूमर सहकारी समितियों का भी अभाव है। पहिले इस तरह के संस्थानों द्वारा देश में अच्छा कार्य किया गया है। इससे मुद्रा स्फीति की समस्या को भी हल किया जा सकता है। देश में व्यापार एवं निर्माण कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से ईज आफ डूइंग बिजिनेस के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसे सहकारी संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में भी काम करना आसान हो सके।

सहकारी संस्थानों को पूंजी की कमी नहीं हो इस हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए। केवल ऋण के ऊपर अत्यधिक निर्भरता भी ठीक नहीं है। सहकारी क्षेत्र के संस्थान भी पूंजी बाजार से पूंजी जुटा सकें ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। विभिन्न राज्यों के सहकारी क्षेत्र में लागू किए गए कानून बहुत पुराने हैं। अब, आज के समय के अनुसार इन कानूनों में परिवर्तन करने का समय आ गया है। सहकारी क्षेत्र में पेशेवर लोगों की भी कमी है, पेशेवर लोग इस क्षेत्र में टिकते ही नहीं हैं। डेयरी क्षेत्र इसका एक जीता जागता प्रमाण है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में नए मंत्रालय का गठन के बाद यह आशा की जानी चाहिए के सहकारी क्षेत्र में भी पेशेवर लोग आकर्षित होने लगेंगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पॉलिटेक्निक एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के खिलाफ भटनी के ग्राम सचिवों का प्रदर्शन

अतिरिक्त विभागीय कार्य थोपे जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी

भटनी देवरिया।

ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश तथा ग्राम पंचायत अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के संयुक्त आह्वान पर दिन सोमवार को भटनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिवों ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली और विभिन्न विभागों द्वारा अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने के विरोध में काला पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रतीकात्मक विरोध सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कुमार शाही के नेतृत्व में आयोजित हुआ। सचिवों ने प्रभारी बीडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की कार्यप्रणाली के अनुरूप ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है। इससे फील्ड निरीक्षण, विकास कार्य तथा पंचायत संचालन की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही अन्य विभागों के अतिरिक्त दायित्व थोपने से सचिवों पर अनावश्यक कार्यभार बढ़ रहा है। संयुक्त संगठन ने घोषणा की है कि 1 से 4 दिसंबर तक सभी सचिव काला पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। आंदोलन के अगले चरण में माननीय मुख्यमंत्री को पत्रक सौंपा जाएगा। यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो सचिवों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कुमार शाही, जयप्रकाश गोंड, जनरंजन गौतम, अजय मिश्रा, जितेंद्र कुमार यादव, दीनदयाल चौहान, शुभम कुमार गुप्ता, यशपाल चौहान, अरुण श्रीवास्तव सहित अनेक ग्राम सचिव मौजूद रहे।

एड्स जागरूकता रैली के साथ मनाया गया विश्व एड्स दिवस

भटनी देवरिया।

राजा देवी महिला पीजी कॉलेज सलहपुर, भटनी में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एनएसएस व रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से छात्राओं ने स्थानीय समुदाय को एचआईवी/एड्स की गंभीरता, बचाव एवं रोकथाम के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अमित कुमार राय ने उपस्थित छात्राओं व समुदाय को संबोधित करते हुए विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम "विघटन पर काबू पाना एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाना, पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, उठ खड़े हों" पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एड्स जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए समाज को एकजुट, जागरूक और संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। डॉ नन्द तिवारी ने एड्स की भयावहता, संक्रमण के तरीकों और बचाव उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी साधन है। कार्यक्रम में राजेश राव ने कहा कि एड्स से बचाव का मूल मंत्र है जानकारी ही सुरक्षा है।

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रीतेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व एड्स दिवस का मुख्य उद्देश्य एचआईवी संक्रमण, एड्स महामारी, उससे होने वाली मृत्यु तथा प्रभावित लोगों की समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर पुनीता मिश्रा, श्रवण पाण्डेय, सत्येन्द्र पाल, अनुज पाण्डेय, संतोष प्रजापति सहित अन्य शिक्षकों व छात्राओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

राजा देवी महिला पीजी कॉलेज में एनएसएस/ रेड रिबन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जल जीवन मिशन के ऑपरेटर अजय पाल की हार्ट अटैक से मौत

कम्हरिया में तैनात थे, सुबह अचानक बिगड़ी तबियत

(मृतक अजय पाल का फाइल फोटो)

भटनी देवरिया।

जल जीवन मिशन में ऑपरेटर पद पर कार्यरत अजय पाल पुत्र नन्दलाल पाल, निवासी कम्हरिया का सोमवार की सुबह लगभग 6 बजे हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया।

उनकी माता का नाम पानमती देवी है। अजय पाल कम्हरिया क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। प्रतिदिन की तरह सुबह उठे, तभी अचानक तेज सीने में दर्द होने पर उनकी स्थिति बिगड़ गई। परिजन इलाज की तैयारी करते, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके आकस्मिक निधन से परिवार एवं क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

स्थानीय लोगों, सहकर्मियों तथा जल जीवन मिशन के कर्मचारियों ने निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और ईश्वर से शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।

विधायक ने किया दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन, खिलाड़ियों को दिए पुरस्कार

कुशीनगर । (वेबवार्ता) युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित विधायक खेल स्पर्धा का दो दिवसीय कार्यक्रम जिला स्टेडियम रविन्द्रनगर में भव्य रूप से शुरू हुआ। मुख्य अतिथि विधायक मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर एथलेटिक्स 800 मीटर दौड़ का शुभारंभ किया। इसमें विशाल यादव प्रथम, प्रदीप जायसवाल द्वितीय और आदित्य उपाध्याय तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में लक्ष्मी यादव प्रथम, कुमारी सलोनी द्वितीय और अमृता सोनी तृतीय स्थान पर रहीं। विजेताओं को विधायक द्वारा मेडल, प्रशस्ति पत्र और टी-शर्ट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला युवा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित कई गणमान्य अधिकारी और खेल प्रशिक्षक उपस्थित रहे। आयोजकों ने अतिथियों का धन्यवाद दिया और कार्यक्रम का संचालन रविन्द्र नारायण पांडेय ने किया। विधायक ने खेलों के माध्यम से स्वस्थ और सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया और क्षेत्र में खेल विकास के प्रयासों की सराहना की।

गडौरा चीनी मिल के संचालन में देरी से 5000 गन्ना किसान प्रभावित

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

जे एच वी गडौरा चीनी मिल के समय पर न चलने के कारण खड्डा और छितौनी क्षेत्र के लगभग 5000 गन्ना किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों की फसल खड़ी होने के बावजूद मिल संचालन में देरी के कारण वे गन्ना गिराकर गेहूं, तोरी और अगले सत्र के गन्ने की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। आरोप है कि गडौरा चीनी मिल प्रशासन और गन्ना विभाग के अधिकारी मिल चालू होने की कोई निश्चित तिथि नहीं बता पा रहे हैं, जिससे किसानों की मौसमी बुवाई प्रभावित हो रही है। पिछले वर्ष भी किसानों को ढुलाई में लापरवाही, भुगतान में देरी और बार-बार मिल बंद होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

दबंगई की हद पार, युवक को बगीचे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, चप्पल पर थूककर चटवाया; वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में

देवरिया।

सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास में दबंगई की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मनबढ़ युवकों ने एक युवक को घर से बुलाकर बगीचे में ले जाकर न केवल बेल्ट से पीटा, बल्कि चप्पल पर थूककर उसे चटवाने जैसी शर्मनाक हरकत भी की। पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित युवक अभिषेक विश्वकर्मा का आरोप है कि कुछ दिन पहले स्थानीय मनबढ़ों से कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में मनबढ़ों ने देख लेने की धमकी दी थी। रविवार की शाम जब अभिषेक घर के बाहर अकेला खड़ा था, तभी आरोपित युवक उसे पास स्थित एक बगीचे में ले गए और बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान बेल्ट से मारते हुए उससे अमानवीय तरीके से चप्पल पर थूक चटवाया गया। मनबढ़ों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की मां ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। स्वजन का आरोप है कि जब वे विरोध जताने पहुंचे तो मनबढ़ों ने उनके घर पर ईंट-पत्थर भी चलाए। कोतवाली सदर प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में चार नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में मनबढ़ों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे शांति-व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में बढ़ती दबंगई की खतरनाक मानसिकता को भी उजागर करती है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बीएलओ व सुपरवाइज़र सम्मानित

देवरिया। विधानसभा निर्वाचन सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में देवरिया सदर विकासखंड के कार्मिकों ने कार्यकुशलता और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। इसी कड़ी में उच्च प्राथमिक विद्यालय पिंडरा देहात की कक्ष संख्या एक पर तैनात बीएलओ विमला देवी (शिक्षामित्र) को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सोमवार को विकासखंड संसाधन केंद्र देवरिया सदर में सम्मानित किया गया। उपजिलाधिकारी देवरिया सदर श्रुति शर्मा ने विमला देवी एवं सुपरवाइज़र अमरेंद्र यादव को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। बीएलओ विमला देवी ने बताया कि उन्होंने नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को लगातार जागरूक करते हुए शत-प्रतिशत एसआईआर का लक्ष्य पूरा किया। इसके लिए उन्होंने घर-घर संपर्क अभियान चलाया, छूटे हुए नामों का सत्यापन किया, मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी अद्यतन की और 1 दिसंबर से पूर्व पूरे बूथ क्षेत्र की पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी की। खंड शिक्षा अधिकारी देव मुनि वर्मा ने बताया कि बीएलओ विमला देवी का कार्य जिले के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे कर्मठ कार्मिकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे भी विशेष पुनरीक्षण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। बीआरसी पर एसआईआर फॉर्म की फीडिंग में सहायता के लिए अध्यापकों और ईसीसीई एजुकेटर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी क्रम में ईसीसीई एजुकेटर गुड़िया चौबे को भी बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीआरसी देवरिया सदर के कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण मे रामकोला विधानसभा आगे

कप्तानगंज(कुशीनगर)। इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण कार्य में जोर शोर से लगे प्रशासनिक अमला के बीच अच्छी खबर है कि कम समय सीमा में काम की अधिकता तथा इस कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों के तनाव में आने की खबरों को संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम तिथि 4 दिसंबर से एक सप्ताह बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। इसके साथ ही रामकोला विधानसभा के लिए अच्छी खबर यह है कि कुशीनगर जनपद में रामकोला विधानसभा लक्ष्य प्राप्ति के दिशा में प्रथम स्थान पर चल रहा है। एसडीएम विनोद गुप्ता के नेतृत्व में एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए बीएलओ की सहायता के लिए तहसील मे कार्यरत लेखपालों का फौज के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, ग्राम रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, ग्राम प्रधान, कोटेदार को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है।

इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के जिम्मेदारो तथा बूथ लेवल एजेंट द्वारा भी सक्रिय रूप से इसमें अपना योगदान दिया जा रहा है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी पोस्ट कर वाहवाही भी लूटी जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों की टीम गांव और कस्बा मे करीब करीब डोर टू डोर अभियान चला रखा है। रविवार 1 तारीख को दोपहर 1:00 बजे तक रामकोला विधानसभा में कुल 378715 मतदाताओं को गणना परिपत्र वितरित हो चुका है तथा इनमें से 275260 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार रामकोला विधानसभा में अब तक 73 प्रतिशत से अधिक लोगों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है जो काफी सुखद रिपोर्ट है। इसके अतिरिक्त मतदाता पुनरीक्षण कार्य के तहत लगभग 24000 मतदाताओं जिनमें से मृतक, अनुपस्थित या दूसरे जगह शिफ्टेड लोगों की संख्या है का नाम सूची से हटा दिया गया है। एसडीएम विनोद गुप्ता ने इस संबंध में बताया कि तहसील के सभी लेखपाल की ड्यूटी सुपरवाइजर के रूप में बीएलओ की सहायता के लिए लगाया गया है जबकि उनके द्वारा खुद लेखपाल से लगायत बीएलओ लेवल तक का मॉनिटरिंग की जा रही है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य के प्रति एसडीएम विनोद गुप्ता की प्रतिबद्धता इससे समझी जा सकती है कि रविवार को भी अपने कार्यालय में काफी सक्रियता के साथ काम करते दिखे तथा फोन पर आवश्यक गाइडलाइन निर्देश देते रहे।

अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक को राहत नहीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जावेद सिद्दीकी, जिन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपों के चलते जावेद को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जावेद सिद्दीकी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अब उन्हें जेल में रहना होगा और इस दौरान जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी (61) तीन वर्ष जेल में बंद रह चुका है। वह पहले चिट फंड का काम करता था। उसके बाद उसने लोगों को पैसे नहीं दिए थे। उसके खिलाफ 14 से 15 प्राथमिकी दर्ज हुई थी। माना जा रहा है कि उसने इन पैसों से यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में लगाया। हालांकि बाद में उसने सभी लोगों का पैसा लौटा दिया। वह सभी केसों से बरी हो गया था। साल 2000 दर्ज हुई एफआईआर (संख्या 43/2000) में सिद्दीकी और उसके भाई सउद अहमद का नाम दर्ज किया गया था, जो नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 और 409 (आपराधिक न्यास का उल्लंघन), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई थी। उन पर 7.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप था। मालिक जावेद ने इंदौर से बीटेक सिविल इंजीनियर में किया हुआ है। इसके बाद उसने वर्ष 1992 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एसिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करना शुरू किया। यहां इसने जनवरी, 1994 तक नौकरी की। इसकी दोनों बहनें दुबई में रहती है। दोनों बेटे भी दुबई में रहते है। जावेद अहमद सिद्दीकी, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष है, जो फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर चलाता है। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संबंध नौ कंपनियों से है, जिसका मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी है। सिद्दीकी इन नौ कंपनियों का डायरेक्टर है, जो कि इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, सॉफ्टवेयर, ऊर्जा, निर्यात और कंसल्टेंसी से जुड़ा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके जावेद अहमद सिद्दीकी, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष है। अल फलाह विश्वविद्यालय अब इस जांच के केंद्र में है। रिकॉर्ड के अनुसार, सिद्दीकी का सबसे पुराना संबंध अल-फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी से है, जिसमें वह 18 सितंबर 1992 को शामिल हुए थे। अन्य कंपनियों में अल-फलाह सॉफ्टवेयर, अल-फलाह एनर्जीज, तर्बिया एजुकेशन फाउंडेशन और अल-फलाह एजुकेशन सर्विस शामिल है, जिसमें वह हाल ही में (26 दिसंबर 2023 को) जुड़े।

अरुणाचल में क्लास-1 में पढ़ने वाली 4 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न, ट्यूशन टीचर गिरफ्तार

ईटानगर।

अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में लगभग छह से सात साल की उम्र की चार बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि इन बच्चों के निजी ट्यूशन टीचर पर ही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप है. पुलिस ने उस शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 9.15 बजे नाहरलागुन पुलिस स्टेशन में एक मौखिक रिपोर्ट मिली,

जिसमें बताया गया कि कक्षा एक की चार छात्राओं के साथ ट्यूशन के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया. आरोपी की पहचान लोअर सुबनसिरी जिले के रहने वाले 35 साल के मिलो तकर के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर नाहरलागुन में उसके किराए के अपार्टमेंट में हुई. उन्होंने बताया कि नाहरलागुन पुलिस स्टेशन की एक टीम, जिसमें सब-इंस्पेक्टर एस. दिनी, हेड कांस्टेबल एस. बगांग और टी. के. खोनी शामिल थे, उन्होंने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महिला पुलिस स्टेशन, ईटानगर को सौंप दिया. पुलिस ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराएं लागू की जाएंगी. आगे की जांच जारी है.

2027 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाना लक्ष्य : सीएम योगी

लखनऊ।

संविधान दिवस पर पेरिस से आई एक विशेष तस्वीर ने पूरे देश, खासकर उत्तर प्रदेश को गर्व से भर दिया। यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव राव... लखनऊ; संविधान दिवस पर पेरिस से आई एक विशेष तस्वीर ने पूरे देश, खासकर उत्तर प्रदेश को गर्व से भर दिया। यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव राव अम्बेडकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 'योगी की पाती' के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया और बाबा साहेब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश को वर्ष 2027 तक गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही है। सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदेश की जनता के नाम संबोधित योगी की पाती पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व समुदाय जब बाबा साहेब के योगदान को सराहता है, तो वह क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का होता है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना को जीवन में उतारने वाले युगांतरकारी महापुरुष थे। शोषित, वंचित और दबे-कुचले वर्गों को अधिकार दिलाने की उनकी कोशिशें आज भी सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलितों, वंचितों और कमजोर तबकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई हैं। शिक्षा, छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाएँ, प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक सहायता-इन सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब की सोच पर चलते हुए प्रदेश में 'जीरो पॉवर्टी अभियान' संचालित किया जा रहा है। इसके तहत कमजोर वर्गों तक आवास, राशन, पेंशन, शिक्षा, श्रम योजनाएँ और बाल विकास कार्यक्रमों का लाभ तेज गति से पहुँचाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है।

वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा लोकसभा, कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली।

संसद के निचले सदन, लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और अब मंगलवार (2 दिसंबर) को सुबह 11 बजे बैठक होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बार-बार नारेबाजी हुई और सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही कुल तीन बार स्थगित हुई और लगभग 50 मिनट का ही विधायी कार्य हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को विचार एवं पारित करने के लिए सदन में पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बार-बार हो रही नारेबाजी के बीच सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, विशेष रूप से वित्त अधिनियम 2025 की धारा 121 से 134 में संशोधन किया है। इसे संसद द्वारा पारित किया गया और 2024 में अधिनियमित किया गया। आधे से अधिक राज्यों द्वारा अपने जीएसटी को अपनाने करने के बाद ये परिवर्तन अक्टूबर 2025 से प्रभावी भी हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर में जीएसटी समय पर लागू नहीं हो सका क्योंकि राज्य विधानसभा निलंबित थी। इस बीच, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सांसद कृष्ण प्रशांत टेनेटी ने विपक्षी सांसदों से शिष्टाचार बनाए रखने और अपनी सीटों पर वापस

जाने का आग्रह किया, जहाँ उनकी बात ठीक से सुनी जा सके। सांसद कृष्ण प्रशांत टेनेटी ने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए कहा कि कृपया बैठ जाएँ। कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएँ, कार्यवाही चलने दें, मैं आपकी बात सुनूँगा लेकिन इस तरह नहीं। कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएँ, ताकि मैं आपकी बात सुन सकूँ, अभी मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। अगर 20-40 लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊँगा। बार-बार अनुरोध के बाद भी नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सांसद ने आगे कहा कि आप अपनी बात सुनना चाहते हैं या नहीं? अगर आप अपनी बात नहीं सुनना चाहते है, तो सदन की कार्यवाही मंगलवार, 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले, कई विपक्षी नेताओं ने सदन में वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए और देश भर में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की। दिन भर यही नारे लगते रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए।

जनता के मुद्दों को उठाना नाटक नहीं : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में लोक महत्व के मुद्दों को उठाना 'नाटक' नहीं है, बल्कि इन पर चर्चा की अनुमति नहीं दिया जाना 'नाटक' है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र राजनीतिक रंगमंच न बने, बल्कि रचनात्मक और परिणामोन्मुखी बहस का माध्यम बने। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''संसद में आवश्यक लोक महत्व के मुद्दों के बारे में बोलना और उन्हें उठाना नाटक नहीं है। नाटक यह है कि उन मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती, जो जनता के लिए मायने

विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने घोषणा पत्र में जो बातें कहीं हैं, उनको पूरा करिए...चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी का वोट बनाए और यह काम हम कर रहे हैं है ताकि हमारे वोट ना कटे...हम अपनी वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं...उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो दिखाई दे रहा है, वो यह है कि भाजपा की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है, उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटे जाएं।

एसआईआर पर बहस के लिए तैयार, समय सीमा न थोपें

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील कि वह इस पर कोई समय सीमा न थोपें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम् पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। यह बहस गुरुवार-शुक्रवार को हो सकती है। पीएम मोदी खुद इसमें हिस्सा ले सकते है। 30 सितंबर को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने इस चर्चा का प्रस्ताव रखा था। अब तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। आज सदन की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी

चाहिए। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। पीएम ने इसके बाद राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उनके अभिवादन में स्पीच दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिवादन किया। खड़गे ने इस दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा- मुझे इस बात का दुख है कि सदन को पूर्व सभापति को फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा- आपको बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। आपको अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, और विपक्ष की बहस की

खड़गे ने कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख; नड्डा बोले- डॉक्टर को तकलीफ बताइए

मांग पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से अपील कि वे इस पर कोई समयसीमा न थोपें। उन्होंने कहा, कल सर्वदलीय बैठक में या आज विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। यह सरकार के विचाराधीन है। यदि आप यह शर्त रखते हैं कि इसे आज ही उठाना होगा, तो यह कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ी गुंजाइश देनी चाहिए। एसआईआर या चुनावी सुधार से जुड़ा मामला हो। आपने जो मांग रखी है उसे खारिज नहीं किया गया है। यह मत मानिए कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।

यूपी में एसआईआर का दबाव नहीं झेल पा रहे बीएलओ, एक और ने दी जान

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में काम के कथित दबाव के चलते बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की ड्यूटी कर रहे एक सहायक अध्यापक ने रविवार को अपने घर के स्टोर रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान भोजपुर के बहेड़ी गांव के एक सहायक शिक्षक सर्वेश सिंह (46) के रूप में हुई है।

सर्वेश भगतपुर टांडा गांव के एक स्कूल में तैनात था। वह सात अक्टूबर को बीएलओ बनाया गया था। तड़के करीब चार बजे सर्वेश की पत्नी बबली ने उसे फांसी पर लटकता पाया। उन्होंने बताया कि मौके पर मिले एक कथित सुसाइड नोट में सर्वेश ने घुटन और डर महसूस करने

का जिक्र करते हुए लिखा है कि बीएलओ के काम के लिए दिया गया समय अपर्याप्त है। ठाकुरद्वारा के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप सिंह ने कहा, बीएलओ सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली है और एक सुसाइड नोट छोड़ा है। जिसमें लिखा है कि वह बीएलओ ड्यूटी का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर सर्वेश का एक वीडियो भी वायरल हो

सुसाइड से पहले बेतहाशा रोते हुए बनाया वीडियो

रहा है। इस वीडियो में सर्वेश कुमार बुरी तरह रो रहे हैं। वह बार-बार काम के दबाव की बात कर रहे है। साथ ही अपनी मां से बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह है। बताया जा रहा है कि सर्वेश ने यह वीडियो सुसाइड से पहले बनाया था। इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो उठे हैं। वीडियो में सर्वेश कुमार बेतहाशा रोते हुए कहते है, मम्मी, मेरी चारों बेटियों का ख्याल रखना। मैं आज जो कदम उठाने जा रहा हूं इसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मेरे परिवार को कोई कुछ नहीं कहेगा। एसआईआर के काम का दबाव बहुत ज्यादा है। न मैं सो पा रहा हूं और ना ही काम कर पा रहा हूं। मैं जीना चाहता हूं लेकिन मेरे ऊपर काम का बहुत दबाव है।

पिनाराई विजयन के घर पर फिर बम की चेतावनी, डार्क वेब से भेजे जा रहे फर्जी ईमेल

केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आधिकारिक आवास पर रिपोर्टर शिबी मोल इस प्रसारण में अपडेट देने के लिए शामिल हुए और पुष्टि की कि सुरक्षा जाँच अभी चल रही है। शिबी मोल ने बताया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि हाल के महीनों में मुख्यमंत्री कार्यालय और पद्मनाभस्वामी मंदिर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इसी तरह की धमकियाँ दी गई हैं। रिपोर्टर ने बताया कि पुलिस को संदेह है कि ये ईमेल, जो संभवतः एक ही आईडी से भेजे गए हैं, बार-बार होने वाली धोखाधड़ी का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि एक ईमेल में दावा किया गया था कि दोनों स्थानों पर बम रखे गए हैं, जिसके बाद 1 दिसंबर को विजयन के आवास और पलायम स्थित एक निजी बैंक की जांच की गई।

तेज रफ्तार बेकाबू बस ने टेंपो को रौंदा, एक ही परिवार के 6 की मौत

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रविवार को तेज रफ्तार एक रोडवेज बस ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि कि यह हादसा रफतपुर अंडरपास के पास 'जीरो पॉइंट' पर उस समय हुआ, जब बस ने पीछे से टेम्पो को टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक, हादसे में संजू (30), सुमन (30), सीमा (35), आरती (20), अमन (15) और अनन्या (12) की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी कुंदरकी थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर के रहने वाले

5 की हालत गंभीर; 15 फीट दूर जा गिरे लोग, दो हिस्से में बंट गया वाहन

थे और रफतपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि घायल हुए पांच लोगों (करण सिंह, रानी, झलक, अंशु और अनुष्का) की हालत गंभीर है और जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

कोलकाता में बीएलओ का भारी विरोध प्रदर्शन, निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ ने सोमवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओ ने कोलकाता में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया। हालात इस कदर बिगड़े कि बीएलओ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

बीते हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने जबरन राज्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा में चूक को बेहद गंभीर बताते हुए निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) काम का भारी दबाव होने का आरोप लगा रहे है। बूथ लेवल अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते उन्हें अमानवीय तनाव झेलना पड़ रहा है। बीएलओ का यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है, जब बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं भारी काम के दबाव के चलते देशभर से कई बीएलओ की मौत होने का दावा किया जा रहा है। परिवारों का आरोप है कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम के दबाव डाला जा रहा है।

चुनाव आयोग ने एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई

वहीं बीएलओ पर काम के भारी दबाव की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन सात दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाने का एलान करते हुए आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, इसके मुताबिक पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म भरे जाने यानी इन्युमेरेशन की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है।

वक्फ प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुझाव दिया कि आवेदक वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष 2025 अधिनियम के अनुसार आवेदन दायर करके उक्त राहत प्राप्त करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि आवेदकों के लिए वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही एक उपाय उपलब्ध है, इसलिए वे 6 दिसंबर तक इसका अनुरोध कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि यह संपत्ति के पंजीकरण की अंतिम तिथि है। आवेदकों की ओर से उपस्थित वकीलों ने दलील दी कि मुद्दा केवल उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके डिजिटलीकरण से भी जुड़ा है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में वास्तविक कठिनाई का सामना करने वाला कोई भी आवेदक ट्रिब्यूनल से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। यदि समय सीमा (पोर्टल में) रुक जाती है, तो आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि ट्रिब्यूनल आपको अनुमति देता है, तो आपके छह महीने गिने जाएंगे और आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कठिनाई आती है, तो आप हमेशा हमारे पास आवेदन कर सकते हैं।